(xiv) Discussion demanded on Press Reports regarding Presidential form of Government in our country

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, आजकल हमारे देश में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की चर्चा हो रही है। केन्द्री सरकार और प्रदेशीय सरकारों के मन्त्री कांग्रेस (आई) और विरोधी पार्टियों के संसद् सदस्य, नेता, अखबार, बुद्धिजीवी और जनता में यह चर्चा है कि शासन प्रणाली बदलनी चाहिए या नहीं। नाना प्रकार की अटकलें और कल्पनाएं की जा रही हैं। पंजाब की स्थिति से देश का हर देशभक्त असाधारण रूप से चिंतित है। सरकार और विरोधी पार्टियां इस राष्ट्रीय समस्या के हल के लिए एक मत नहीं। लोग कहते हैं यदि राष्ट्रपति का चुनाव पूरे देश की जनता द्वारा होगा तो राष्ट्रीय स्तर का ही नेता चुनाव लड़ेगा। वह कभी देश का बटवारा नहीं चाहेगा। किस नेता या पार्टी की सरकार बनेगी यह बात साधारण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार भारत और पाकिस्तान बनने के बाद कोई इस बात की कल्पना भी न कर पाए की देश का विभाजन भी हो सकता है। क्या यह विषय सरकार के प्रम्मुख विचाराधीन है, बताए ?

सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इस विषय पर संसद् में खुलकर बहस कराए और वक्तव्य दें ताकि जनता को विचार करने का अवसर मिले या इस विषय पर आगे जनता की राय जाने।

(xv) Crisis in Steel re-rolling units

SHRI LAKSHMAN MALLICK (Jagatsinghpur) : The steel re-rolling industry has been reeling under a severe cvisis since last three years. The reasons of crises are not far to seek. The non-availability of major inputs like coal and power have led to the crises of the industry. The prices of coal have gone up by over 400 per cent in less than a decade. The average price of steam coal per tonne comes to Rs. 270 after last increase effectiee from January 8, this year. Even at these high prices, coal is not available in adequate quantity, in right quality and in right weight. Power shortage is more or less a common problem in every State and due to this, power cut has beeu imposeed on the steel re-rolling units.

The industry would restore its health if the following measures are taken up with all seriousness by the appropriate authorities.

Prices of all basic materials should not be allowed to increase at least for two years. Joint plant committee of the main producer should so fix the rates of semis ensuring that re-rollers get the conversion cost as fixed by it for the integrated steel plants. Arrangements should be made to supply major essential inputs of the steel re-rolling uniis at reasonable rates. I request the hon. Miuister of Steel and Mines to take immediate steps in the above matter and make an end to the crises in steel re-rolling units.

(xvi) Steps Needed to Same MAMC, Durgapur from Closure

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Dugapur) : M.A.M.C., Durgapur, a Government of India Undertaking under Minitery of Industry, is starving for orders, and from 1985, the position of the industry is very weak, if no order is forthcoming through Government initiative.

The company can very well meet the requirement of CIL subsidiaries for mining equipments. It is really shocking that the CIL subsidiaries, and

also the apex bodies of these subsidiaries, as it seems, are not really inclined to place orders on M.A.M.C. As a result, the industry is unable to make full utilization of its capacity. As you are aware, the Government of India have had a clear formulation for purchase and price preference in respect of placement of orders from one public sector to another public sector. This policy is also not being pursued in its real sprit.

I have already requested the Energy Minister regarding placement of orders for Madhuban Coal Washery under SCCL on MAMC, because the order amounting to Rs. 60 crores is being placed on private/foreign firm though MAMC was the lowest tenderer. I again like to mention that the order for coal handling plant for vindhyachal Projcet under NIPC valued at Rs. 30 crores, was initally placed under a private scetor comany, ignoring the claim and reasonableness of MAMC ; and when MAMC protested, the customer awarded the contract to another public sector unit, who has no expertise in this field.

If this sort of a situation is thrust upon MAMC , it will not only effect the existance of MAMC. adversely, but will also cause an erosion into the already built-up infrastructure in this Durgapur belt, including the small scale and ancillary innustries, as no further industry has been set up by Government of India in this belt for the last 20 years.

So, I urge upon the concerned Minister to take approiate steps.

(xvii) Scarcity of Vanaspati in the country

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, देश के विभिन्न भागों विशेषकर दिल्ली में वनस्पति घी की भारी कमी पैदा हो गई है । खाद एवम नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कमी निकटभविष्य में दूर होने वाली नहीं है क्योंकि वनस्पति घी बनाने वाली मिलों को कच्चा माल और आयातित खाने का तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । उत्पादन में कमी होने की वजह से बाजार में भी माल कम सप्लाई किया जा रहा है । आम जनता की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह वनस्सपति निर्माताओं को निर्देश दे कि वे सरकार द्वारा नामांकित ऐजेन्सियों जैसे सुपर बाजार, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन और कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव्ज आदि को ही माल सप्लाई करने में वीरयता दें और जो व्यापारी जखीरेबाजी तथा ब्लैक करने के दोषी पाये जाएं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायें ।

(xviii) Demand for an Express Train between Delhi and Sikar (Rajastan) vis Lohare.

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, पिछले कई वर्षों से सीकर व झुन्झुनू (राजस्थान) के निवासी सीकर से दिल्ली वाया लुहारू एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की लगातार मांग करते आ रहे हैं । मैंने भी कई बार सदन में बहस के दौरान सीकर-दिल्ली रेलगाड़ी चलाने की मांग रखी । इस समय सीमर से दिल्ली के लिए एक कोच पहला व दूसरा दर्जा का व एक कोच दूसरा दर्जा तीन टीयर शयन का उत्तर रेलवे 91, पश्चिम रेलवे 28 में लगाये जाते हैं । ये काफी नहीं हैं, इनमें भेड़बकरी की तरह मुसाफिर घुसते हैं और सोना तो दूर रहा, खड़े-खड़े भी दिल्ली आना कठिन होता है । जिनको इन डिब्बों में जगह नहीं मिलती उन्हें लुहारू जंक्शन पर आधी रात